

प्रकाशनार्थ / प्रसारणार्थ

राज्यों की रैंकिंग में बिजली के मामले में बिहार छठे स्थान पर— उपमुख्यमंत्री

पटना 04.01.2019

बिहार इलेक्ट्रिक टेडर्स एसोसिएशन की ओर से पटना न्यू क्लब में आयोजित चार दिवसीय 'इलेक्ट्रिकल ट्रेड शो' का शुभारंभ करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक बिजली के मामले में सबसे निचले पायदान पर रहने वाला बिहार इस साल निति आयोग द्वारा राज्यों की रैंकिंग में पूरे देश में छठे स्थान पर है। सभी गांवों व 1.6 लाख टोलों में बिजली पहुंच जाने के बाद 2005 में जहां राज्य के मात्र 24 लाख घरों में बिजली के कनेक्शन थे वहीं अब वह बढ़ कर 1.39 करोड़ हो गया है। 2005 में राज्य में बिजली की कुल मांग पीक ऑवर में मात्र 700 से 900 मेगावाट थी जो अब बढ़ कर 5,139 मेगावाट हो गई है। राज्य की बिजली वितरण की क्षमता 10 हजार मेगावाट है। सरकार ने इस साल दिसम्बर तक बिजली के सभी जर्जर तारों को बदलने का निर्णय लिया है।

श्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार के 6 हजार करोड़ से दिसम्बर 2019 तक अलग कृषि फीडर स्थापित कर किसानों को खेती के लिए 6 से 8 घंटे बिजली की आपूर्ति की जायेगी। बिजली आधारित सिंचाई से कृषि लागत कम होगी और किसानों की आमदनी दोगुनी करने में मदद मिलेगी।

प्री पेड बिजली मीटर लगाने का काम पटना में प्रारंभ हो चुका है, अगले दो साल में पूरे प्रदेश में प्री पेड मीटर लगाने का लक्ष्य है। उपभोक्ता मोबाइल एप से रिचार्ज और पेमेंट कर सकेंगे। इससे बिल का झंझट खत्म होगा और इसका सर्वाधिक लाभ गरीबों को मिलेगा।

पिछले 5 वर्षों में बिजली पर 55 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। राज्य सरकार बिजली उपभोक्ताओं को 2015-16 में सरकारी खजाने से 5 हजार करोड़ तथा इस साल 4 हजार करोड़ रुपये अनुदान दिए गए हैं। बिजली की चोरी व ट्रांसमिशन लॉस 2016-17 की 42 प्रतिशत से घट कर 2017-18 में 34 प्रतिशत और 2018-19 में 28 प्रतिशत रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में इसे और कम करने की कोशिश की जा रही है।

जीएसटी लागू होने के बाद बिजली सामानों पर कर की दर 28 से घट कर 18 प्रतिशत रह गयी है। जीएसटी के तहत राज्य के 4,592 डीलर निबंधित हैं। राज्य के कर संग्रह में बिजली कारोबारी 7वें स्थान पर हैं।